अब सरकारी दफ्तरों की दौड़ कम, ऑनलाइन काम ज्यादा

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजना लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों में दौड़भाग करने वालों की तादाद तेजी से कम हो रही है। ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। यही नहीं निवेशकों की आनलाइन सेवाओं से संतुष्टि स्तर भी बढ़ रहा है।

राज्य में निवेश करने वाले उद्यमी मानते हैं कि पहले जहां विभिन्न प्रकार के लाइसेंस व अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए काफी चक्कर काटने पड़ते थे, अब आनलाइन काम होने से समय बचता है। साथ ही इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता। 145 औद्योगिक क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत साल 2019-20 में प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकारी कार्यालयों में दौड़भाग करने वालों की तादाद 52 प्रतिशत थी।

साल 2021-22 में घटकर यह केवल 10 प्रतिशत ही रह गई। अब निवेशकों के 90 प्रतिशत आवेदन का समाधान आनलाइन हो रहा है।

निवेशकों से लिए फीडबैक के आधार उनकी संतुष्टि स्तर तीन साल में 79 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत पहुंच गया।

ऑनलाइन स्वीकृतियां

आनलाइन आवेदन	4.9 लाख
निस्तारित आवदेन	4.7 लाख
शिकायत निवारण	32442
निवेशकों का फीडबैक	80 % संतुष्ट

■ निवेशकों की परियोजनाएं ऑनलाइन हो रहीं मंजूर

निवेश परियोजनाओं के लिए आवेदन

वित्तीय वर्ष	प्राप्त	निस्तारण
2021-2022	11000	91%
2020-2021	7765	89%
2019-2020	1941	68%
2018-2019	826	40%

349 ऑनलाइन सेवाएं निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं

पहले बहुत दौड़-भाग थी : अवधेश अग्रवाल

आईआईए के मंडलीय अध्यक्ष व उद्यमी अवधेश अग्रवाल ने 2008 में लखनऊ में ट्रांसफार्मर्स के पार्ट बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। वह बताते हैं-उस वक्त निवेश मित्र पोर्टल नहीं था। हर एनओसी के लिए अलग-अलग विभागों में दौड़ना पड़ता था। उसमें काफी वक्त लग जाता था। यहां तक बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में ही कई जगह चक्कर काटने पड़ते थे। अब हालात काफी बेहतर हो गए हैं।

इनका कहना है

- फ्लिपकार्ट के चीफ कारपोरेट आफिसर रजनीश कुमार कहते हैं 'यूपी में निवेशकों के प्रोजेक्ट बिना भागदौड़ के मंजूर हो रहे हैं।'
- कोसीकलां मथुरा में एयर लिक्विड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रसून लोध कहते हैं-'ऑनलाइन आवेदन एक हफ्ते में यह मंजूर हो गया।'
- बाराबंकी ब्रिटानिया के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय सिंह-'निवेश मित्र पोर्टल से उन्हें सहूलियत मिलीं।'
- संडीला-हल्दीराम कंपनी के यूनिट हेड सौरभ बोले-'आनलाइन सेवाओं से हमारा प्रोजेक्ट तय समय में मंजूर हो गया।'
- बाराबंकी गोदरेज कंपनी के यूनिट हेड वेंकटेश ने कहा-'सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए बेहतरीन काम हुआ है।'

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आनलाइन सेवाओं को दो से बढ़ा कर 35 तक पहुंचा दिया। अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि किसी निवेशक को कहीं आना-जाना न पड़े। तय समय सीमा में उसे लाइसेंस व एनओसी दी जा रही है।

-मयूर माहेश्वरी एमडी- यूपीसीडा